भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 389

दिनांक 22 जुलाई, 2025

बिहार में कृषि अनुसंधान

389. श्रीमती लवली आनंद:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की विशेष पैकेज योजना के अंतर्गत बिहार में कृषि अनुसंधान के लिए कोई कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है;
(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक ऐसी सभी परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग) : बिहार-2015 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पैकेज में कृषि अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित दो परियोजनाएं/ स्कीमें शामिल थी:

(i) राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (बिहार) को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्तर के रूप में उन्नयन करना।
(ii) राष्ट्रीय समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र, मोतिहारी, बिहार

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को दिनांक 28/05/2016 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के तहत यह संस्थान राष्ट्रीय महत्व का है और यह अपने 08 महाविद्यालयों के माध्यम से मात्स्यिकी, मौलिक, मानविकी और सामुदायिक विज्ञान, कृषि व्यापार और वानिकी सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार संबंधी कार्यों को संपादित कर रहा है। वर्ष 2015-16 से विश्वविद्यालय को रूपये 1492.23 करोड़ की राशि आबंटित की जा चुकी है।

- भाकृअनुप-महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान (MGIFRI), मोतिहारी, बिहार को रूपये 30.00 करोड़ के परिव्यय के साथ दिनांक 20 जुलाई, 2015 को अनुमोदन प्रदान किया गया था और तदनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे तथा मानवशक्ति के साथ इसे स्थापित किया गया। संस्थान द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली पर कृषि अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 से संस्थान को रूपये 68.94 करोड़ की राशि आबंटित की जा चुकी है।

****